नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 281
दि. 14.07.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

गुजरात में चांदीपुरा वायरस का बढ़ता खतरा, एक महीने में 12 बच्चों की मौत, कई जिलों में हाई अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग की निगरानी तेज

गोधरा। गुजरात में चांदीपुरा वायरस को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले एक महीने के दौरान राज्य में संक्रमण के संदिग्ध मामलों के बीच 12 बच्चों की मौत ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। इनमें से तीन बच्चों में चांदीपुरा वायरस संक्रमण की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, जबकि नौ अन्य बच्चों की मौत भी इसी संक्रमण से होने की आशंका जताई जा रही है। उनके नमूनों की जांच जारी है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। संक्रमण के मामले गांधीनगर, साबरकांठा, खेड़ा, अरावली और पंचमहल सहित कई जिलों में सामने आने के बाद राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी, सर्विलांस और रोकथाम संबंधी गतिविधियां तेज कर दी हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जिला प्रशासन, अस्पतालों और चिकित्सा टीमों को पूरी सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार चांदीपुरा वायरस के मामलों में अचानक आई बढ़ोतरी को देखते हुए राज्यभर में विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्ध लक्षण वाले बच्चों की तुरंत पहचान कर उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है और उनके नमूने जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजे जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती चरण में संक्रमण की पहचान और समय पर उपचार गंभीर स्थिति को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने स्थिति की समीक्षा करते हुए बताया कि अब तक तीन बच्चों की मौत चांदीपुरा वायरस संक्रमण के कारण होने की पुष्टि हुई है। इनमें दो बच्चों की मौत गोधरा में हुई, जबकि राजस्थान के एक बच्चे की मृत्यु हिम्मतनगर में उपचार के दौरान हुई। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रही है और प्रभावित क्षेत्रों में संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीमें गांवों और शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर रही हैं तथा लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है।

स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार जिन नौ

बच्चों की मौत हुई है, उनमें भी चांदीपुरा वायरस जैसे लक्षण पाए गए थे। इन मामलों की पुष्टि के लिए नमूनों की जांच की जा रही है। हिम्मतनगर सिविल अस्पताल में ऐसे छह बच्चों की मौत दर्ज की गई है, जबकि गोधरा सिविल अस्पताल में तीन बच्चों की जान गई है। गोधरा में जिन दो बच्चों की हाल ही में मौत हुई, उनकी उम्र क्रमशः एक वर्ष और दो वर्ष थी। चिकित्सकों का कहना है कि छोटे बच्चों में संक्रमण तेजी से गंभीर रूप ले सकता है, इसलिए समय पर उपचार अत्यंत आवश्यक है।

अब तक राज्यभर से 27 संदिग्ध मरीजों के नमूने जांच के लिए गांधीनगर स्थित प्रयोगशाला भेजे गए हैं। इनमें से 19 नमूनों की जांच पूरी हो चुकी है। जांच रिपोर्ट में सात बच्चों में चांदीपुरा वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन सात संक्रमित बच्चों में से तीन की मृत्यु हो चुकी है, जबकि चार बच्चों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। शेष आठ नमूनों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सभी रिपोर्ट आने के बाद संक्रमण की वास्तविक स्थिति और अधिक स्पष्ट हो सकेगी।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक भी आयोजित की। बैठक में संक्रमण की वर्तमान स्थिति, अस्पतालों की तैयारियों, जांच व्यवस्था, दवा उपलब्धता और रोकथाम संबंधी उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी संदिग्ध मामले में जांच और उपचार में देरी न हो तथा जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह सक्रिय रखा जाए।

पंचमहल जिला फिलहाल सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है। मंडल उपनिदेशक डॉ. सुरेंद्र जैन के अनुसार जिले में अब तक चांदीपुरा वायरस के 13 संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। गोधरा सिविल अस्पताल में फिलहाल पांच बच्चों का उपचार जारी है और उनके नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। इनमें से चार बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है तथा उनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। महिसागर जिले का एक बच्चा गंभीर अवस्था में वेंटिलेटर पर भर्ती है। इसके अलावा पंचमहल के तीन अन्य बच्चों का इलाज वडोदरा स्थित एसएसजी अस्पताल में चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है, हालांकि अंतिम पुष्टि के लिए जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। एक बच्चे को स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है।

साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर सिविल अस्पताल में भी संक्रमण के कई संदिग्ध मामले सामने आए हैं। अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. आशीष जैन ने बताया कि 26 जून से 13 जुलाई के बीच अस्पताल में कुल नौ संदिग्ध मामले दर्ज किए गए। इनमें छह बच्चों की मौत हो चुकी है। एक बच्चा पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट चुका है, जबकि भर्ती दो अन्य बच्चों में से एक की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अन्य मामलों की निगरानी और जांच लगातार जारी है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार चांदीपुरा वायरस मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है और इसमें तेज बुखार, उल्टी, दौरे पड़ना, अत्यधिक कमजोरी तथा मस्तिष्क संबंधी लक्षण तेजी से विकसित हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, क्योंकि शुरुआती उपचार गंभीर जटिलताओं के जोखिम को कम कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से स्वास्थ्य टीमों को सक्रिय किया गया है ताकि संदिग्ध मरीजों की शीघ्र पहचान की जा सके।

संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावित क्षेत्रों में घर-घर सर्वेक्षण, जागरूकता अभियान और कीट नियंत्रण संबंधी गतिविधियां भी तेज कर दी गई हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बच्चों में बुखार या तंत्रिका संबंधी लक्षण मिलने पर तुरंत चिकित्सा परीक्षण कराएं। साथ ही लोगों से घरों और आसपास साफ-सफाई बनाए रखने, बच्चों को अस्वच्छ वातावरण से दूर रखने तथा बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर स्वयं उपचार करने के बजाय तत्काल चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की गई है।

स्वास्थ्य विभाग लगातार सभी जिलों से रिपोर्ट प्राप्त कर स्थिति की समीक्षा कर रहा है। जिला अस्पतालों में बाल रोग विशेषज्ञों की उपलब्धता, आवश्यक दवाओं, आईसीयू और वेंटिलेटर सुविधाओं की भी निगरानी की जा रही है। राज्य सरकार का कहना है कि स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर पहचान, त्वरित उपचार और जनजागरूकता इस संक्रमण से बचाव के सबसे प्रभावी उपाय हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के लक्षणों को नजरअंदाज न करें और बच्चों के स्वास्थ्य में अचानक बदलाव दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। सरकार का कहना है कि जांच, निगरानी और उपचार की पूरी व्यवस्था सक्रिय है तथा सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि संक्रमण पर शीघ्र नियंत्रण पाया जा सके और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

जून में महंगाई ने बढ़ाई आम आदमी की चिंता, खुदरा मुद्रास्फीति 4.38% पर पहुंची, खाद्य वस्तुओं से लेकर सोना-चांदी तक महंगे

नई दिल्ली। देश में महंगाई का दबाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। जून 2026 के खुदरा महंगाई (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-सीपीआई) के ताजा आंकड़ों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.38 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 4 प्रतिशत के मध्यम अवधि के लक्ष्य से अधिक है। हालांकि यह अभी भी आरबीआई के 2 से 6 प्रतिशत के स्वीकार्य दायरे के भीतर है, लेकिन लगातार छठे महीने महंगाई में दर्ज हुई बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि रोजमर्रा के खर्च का बोझ धीरे-धीरे बढ़ रहा है। खाद्य वस्तुओं, सब्जियों, मसालों और आभूषणों की कीमतों में तेजी ने महंगाई को ऊपर धकेलने में प्रमुख भूमिका निभाई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मई 2026 में खुदरा महंगाई दर 3.93 प्रतिशत थी, जो जून में बढ़कर 4.38 प्रतिशत हो गई। यानी केवल एक महीने में महंगाई में 0.45 प्रतिशत अंक की वृद्धि दर्ज की गई। यह पिछले पांच महीनों में पहली बार है जब खुदरा महंगाई आरबीआई के 4 प्रतिशत के लक्ष्य को पार कर गई है। हालांकि केंद्रीय बैंक के निर्धारित सहनशीलता दायरे के भीतर होने के कारण

फिलहाल इसे नियंत्रण से बाहर की स्थिति नहीं माना जा रहा, लेकिन लगातार बढ़ते रुझान ने आर्थिक विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया है। इस वर्ष की शुरुआत में महंगाई अपेक्षाकृत नियंत्रित स्थिति में थी। जनवरी 2026 में खुदरा महंगाई घटकर 2.74 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। इसके बाद फरवरी में यह 3.21 प्रतिशत, मार्च में 3.40 प्रतिशत, अप्रैल में 3.48 प्रतिशत, मई में 3.93 प्रतिशत और जून में 4.38 प्रतिशत दर्ज की गई। इस क्रम से स्पष्ट है कि पिछले छह महीनों से महंगाई लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी, मौसमी प्रभाव और कुछ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति संबंधी चुनौतियों ने इस बढ़ोतरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में आई तेजी रही। जून में खाद्य महंगाई बढ़कर 5.32 प्रतिशत हो गई, जबकि मई में यह 4.78 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई 5.45 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 5.09 प्रतिशत दर्ज की गई। इसका सीधा असर घरों के मासिक बजट पर पड़ रहा है, क्योंकि भोजन और रसोई से जुड़ी वस्तुएं हर परिवार की नियमित आवश्यकता होती हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महंगाई बढ़ने का रुझान देखने को मिला। ग्रामीण क्षेत्रों की कुल खुदरा महंगाई मई के 4.25 प्रतिशत से बढ़कर जून में 4.74 प्रतिशत हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.53 प्रतिशत से बढ़कर 3.92 प्रतिशत दर्ज की गई। ग्रामीण इलाकों में खाद्य वस्तुओं पर अधिक निर्भरता होने के कारण वहां महंगाई का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक दिखाई दिया।

खाद्य वस्तुओं में सबसे अधिक तेजी अदरक और टमाटर की कीमतों में दर्ज की गई। जून में अदरक की महंगाई दर 50.41 प्रतिशत रही, जबकि मई में यह 32.50 प्रतिशत थी। यानी केवल एक महीने में अदरक की कीमतों में उल्लेखनीय उछाल आया। इसी तरह टमाटर की महंगाई दर 31.92 प्रतिशत दर्ज की गई, जिससे घरेलू रसोई का बजट प्रभावित हुआ। मानसून के दौरान आपूर्ति में कमी और परिवहन लागत बढ़ने को इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का प्रमुख कारण माना जा रहा है। हालांकि सभी खाद्य वस्तुओं की कीमतें नहीं बढ़ीं। कुछ सब्जियों में उपभोक्ताओं को राहत भी मिली। आलू की महंगाई दर -20.34 प्रतिशत रही, जिसका अर्थ है कि पिछले वर्ष की तुलना में इसके दाम कम रहे। इसी प्रकार मटर की महंगाई दर -9.67 प्रतिशत दर्ज की गई। इससे संकेत मिलता है कि कुछ कृषि उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता के कारण उनकी कीमतों में कमी बनी हुई है।

महंगाई केवल खाद्य वस्तुओं तक सीमित नहीं रही। गैर-खाद्य वस्तुओं में भी कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। किशमिश और मुनक्का की महंगाई दर 20.52 प्रतिशत रही। वहीं कीमती धातुओं में लगातार तेजी जारी रही। चांदी के आभूषणों की महंगाई दर 133.21 प्रतिशत दर्ज की गई, जो सबसे अधिक रही। इसके अलावा सोना, हीरा और प्लैटिनम के आभूषणों की महंगाई 36.82 प्रतिशत रही।

बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए सरकार बनी सहारा, पालनपुर हलपतिवास में तत्काल राहत; प्रत्येक पात्र परिवार को 6,800 की आर्थिक सहायता

सूरत। 7 जुलाई को हुई रिकॉर्ड बारिश और उसके बाद आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों के राहत एवं पुनर्वास कार्यों को तेज करते हुए गुजरात सरकार ने सूरत के पालनपुर गांव स्थित हलपतिवास क्षेत्र के प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी शुरू कर दी है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों का सर्वे पूरा करने के बाद प्रत्येक पात्र परिवार को 6,800 की नकद राहत सहायता वितरित की। सरकार का कहना है कि यह सहायता प्रारंभिक राहत के रूप में दी जा रही है, जबकि आगे भी आवश्यकता के अनुसार प्रभावित नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

गौरतलब है कि 7 जुलाई को सूरत में कुछ ही घंटों के भीतर 18 से 20 इंच तक रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई थी। मूसलाधार वर्षा के कारण शहर के अनेक क्षेत्रों में जलभराव की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पालनपुर गांव के वार्ड नंबर-9 स्थित हलपतिवास में भी बड़ी संख्या में मकानों में पानी

घुस गया, जिससे लोगों के घरेलू सामान, फर्नीचर, कपड़े, खाद्यान्न और अन्य जरूरी वस्तुओं को भारी नुकसान पहुंचा। कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी थी।

बारिश थमने के बाद राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत सर्वे शुरू किया। अधिकारियों ने घर-घर जाकर नुकसान का आकलन किया और पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की, ताकि राहत राशि शीघ्र उपलब्ध कराई जा सके।

सूरत महानगरपालिका की स्लम सुधार समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बारड ने बताया कि गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष एवं सूरत पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूर्णेश मोदी के मार्गदर्शन तथा राज्य सरकार के संवेदनशील दृष्टिकोण के तहत राहत कार्यों को प्राथमिकता दी गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनीं और राहत व्यवस्था की समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं है, बल्कि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द सामान्य जीवन में वापस लाना भी है। इसी उद्देश्य से राहत वितरण की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाया गया, ताकि जरूरतमंद परिवारों तक सहायता बिना किसी अनावश्यक देरी के पहुंच सके।

राहत वितरण कार्यक्रम के दौरान अदाजन मामलतदार कार्यालय तथा तलाटी की टीम मौके पर मौजूद रही। प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में पात्र परिवारों को निर्धारित सरकारी सहायता राशि वितरित की गई। पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई ताकि वास्तविक प्रभावित परिवारों को ही राहत का लाभ मिल सके।

कार्यक्रम में स्लम सुधार समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बारड, स्थानीय पार्षद हिनाबेन टैंक तथा वार्ड कार्यकर्ता अरविंद काचा सहित कई जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों ने प्रभावित परिवारों से बातचीत कर उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है और राहत एवं पुनर्वास कार्य पूरी गंभीरता से जारी रहेंगे।

प्रशासन का कहना है कि जिन परिवारों को प्रारंभिक सहायता प्रदान की गई है, उनके अलावा अन्य प्रभावित नागरिकों की भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। यदि किसी परिवार को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होगी तो संबंधित विभागों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अन्य सरकारी योजनाओं के तहत भी पात्र परिवारों को राहत उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

रथ यात्रा आयोजन को मिलेगा सरकारी सहयोग, बंगाल में 60 समितियों को पांच-पांच लाख का अनुदान, श्रद्धालुओं के लिए विशेष सेवा केंद्र भी बनेंगे

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने आगामी रथ यात्रा महोत्सव को लेकर बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य की 60 प्रमुख रथ यात्रा समितियों को पांच-पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। 16 जुलाई को आयोजित होने वाले रथ यात्रा उत्सव से पहले की गई इस घोषणा को राज्य सरकार की ओर से धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को संस्थागत सहयोग देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही राज्यभर में लगने वाले प्रमुख रथ यात्रा मेलों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां स्वास्थ्य, प्राथमिक उपचार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

राज्य सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय समन्वय बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने यह घोषणा करते हुए कहा कि रथ यात्रा केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का भी महत्वपूर्ण प्रतीक है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा में शामिल होते हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी केवल सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि आयोजन को व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए भी सक्रिय भूमिका निभानी आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष राज्य की 60 चयनित रथ यात्रा समितियों को पांच-पांच लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा, ताकि वे बेहतर ढंग से आयोजन कर सकें। इस आर्थिक सहायता का उपयोग रथ निर्माण, सजावट, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता,

श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास में किया जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आयोजन में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

बैठक में रथ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं, अग्निशमन व्यवस्था और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि सभी प्रमुख आयोजन स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल, यातायात कर्मी, चिकित्सा दल और आपातकालीन सेवाएं पहले से तैनात रखी जाएं। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति से तत्काल निपटने के लिए नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में अधिकांश मामलों में सरकार की भूमिका केवल सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित रहती थी, लेकिन वर्तमान सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को व्यापक जनसहभागिता का अवसर मानते हुए आयोजन समितियों के साथ सीधे समन्वय स्थापित कर रही है। उनका कहना था कि राज्य सरकार का उद्देश्य किसी भी परंपरा में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि आयोजनों को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है।

रथ यात्रा के दौरान राज्यभर में लगने वाले 75 पारंपरिक मेलों में विशेष 'सेवा केंद्र' स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर प्राथमिक चिकित्सा, पेयजल, विश्राम, खोया-पाया सहायता, आपातकालीन जानकारी और आवश्यक मार्गदर्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। बड़ी संख्या में आने वाले बुजुर्ग श्रद्धालुओं, महिलाओं और बच्चों को विशेष सहायता प्रदान करने की भी व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीमों को आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के साथ तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा नगर निकायों और जिला प्रशासन को साफ-सफाई, पेयजल आपूर्ति, अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था तथा कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली विभाग को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और सार्वजनिक निर्माण विभाग को यात्रा मार्गों की मरम्मत तथा बैरिकेडिंग समय पर पूरी करने को कहा गया है। अग्निशमन विभाग भी संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बनाए रखेगा।

प्रशासन का अनुमान है कि इस वर्ष राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित रथ यात्रा और उससे जुड़े मेलों में लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। इसे देखते हुए रेलवे, परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय बढ़ाया गया है, ताकि अतिरिक्त बसों और आवश्यक यातायात सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके। प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था भी पहले से तय की जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी न हो।

रथ यात्रा बंगाल के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। कोलकाता सहित हावड़ा, हुगली, नदिया, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना सहित अनेक जिलों में यह उत्सव बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ के दर्शन और रस्सी खींचने को शुभ माना जाता है, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन में भाग लेते हैं।

सरकार का मानना है कि धार्मिक आयोजनों के सफल संचालन के लिए प्रशासन, आयोजन समितियों और स्थानीय लोगों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। इसी उद्देश्य से संबंधित सभी विभागों को समयबद्ध तैयारियां पूरी करने और आयोजन के दौरान निरंतर निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार को उम्मीद है कि वित्तीय सहायता, बेहतर प्रबंधन और श्रद्धालुओं के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं के माध्यम से इस वर्ष की रथ यात्रा अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और भव्य रूप में संपन्न होगी।

संपादकीय

सैकड़ों स्रोतों से प्रदूषित होती पंजाब की नदियां

शासन-प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद आज भी पंजाब की नदियों को जहरीला बनाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जिसकी पुष्टि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्वीकृति है कि आज भी आठ सौ से अधिक प्रदूषण के स्रोत राज्य की नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। निश्चय ही यह तथ्य उन विभागों व संस्थाओं के कामकाज पर सवालिया निशान है जो पर्यावरण संरक्षण के प्रबंधन से जुड़े हैं। साथ ही लंबे समय से अदालत के हस्तक्षेप व विभिन्न सर्वेक्षणों में सामने आए तथ्यों की पुष्टि होती है कि राज्य में जागरूकता की कमी नहीं है, बल्कि समय रहते प्रभावी कार्रवाई न होने से उपजा संकट है। वर्षों से सरकारें एक्शन प्लान बनाने के दावे करती रही हैं। कभी ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की बात होती है तो कभी कमेटियां बनाने के दावे होते हैं। आखिर क्यों आज भी बिना साफ किया हुआ सीवेज और औद्योगिक कचरा सतलुज, ब्यास और इनकी सहायक नदियों में बदस्तूर बहाया जा रहा है। जाहिर है, मौजूदा संसाधनों का या तो पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है या उनका रखरखाव ठीक नहीं है। फलतः जन-स्वास्थ्य से जुड़ा एक बड़ा संकट पैदा होता है। जो धीरे-धीरे आपदा का रूप ले लेता है। आज फैक्ट्रियों से निकलने वाले रसायनों के जरिये भारी धातुएं और जहरीले तत्व भूजल को प्रदूषित करने के बाद, हमारी खाद्य श्रृंखला में शामिल हो रहे हैं। जो राज्य के बहुचर्चित 'कैंसर बेल्ट' के रूप में हमारे सामने मौजूद है। निस्संदेह, पंजाब में यदि हरित क्रांति का परचम लहराया तो उसके मूल में पंजाब की नदियों की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन आज वे तंत्र की काहिली, अनियोजित शहरीकरण, नियम-कानूनों का क्रियान्वयन न होने और दोषियों को सजा न मिलने का दंड चुका रही हैं। एनजीटी गाहे-बगाहे नगर निकायों की शिथिलता दर्शाकर सच्चाई से आम लोगों को अवगत कराता रहा है। निस्संदेह, पर्यावरण संरक्षण के प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकते हैं जब तक कि इसकी जिम्मेदारी तय न की जाए और सख्त जुर्माना लगाना पर्यावरण संरक्षण नीति का हिस्सा नहीं बनता है। राज्य ने साबित किया है कि मरणासन्न नदियों को फिर से जीवित किया जा सकता है। काली बेईं को पुनर्जीवित करने में जागरूक लोगों की बड़ी भूमिका रही है। जो दर्शाता है कि पक्के इरादे के साथ किए गये प्रयास से बेहद बुरे हालात में पहुंच चुके जल स्रोत को भी जीवंत बनाया जा सकता है। लेकिन इक्का-दुक्का सफलताएं ही व्यापक रणनीति की जगह नहीं ले सकतीं। जरूरी है कि नियम-कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाए, सार्वजनिक रिपोर्टिंग को पारदर्शी बनाएं तथा सीवेज एवं कचरा-शोधन प्रणालियों में निरंतर निवेश बढ़ाया जाए। सर्वविदित है कि पंजाब का नाम यहां की नदियों से पड़ा है। ऐसे में इन नदियों को खुले नाले बनते रहने देने से न केवल हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र व लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि राज्य की खुशहाली व पहचान के लिये भी एक खतरा है। अब मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाने का वक्त है।

स्वयं सहायता समूहों से सशक्त होंगे वरिष्ठ नागरिक

> आज हजारों वरिष्ठ नागरिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इस मॉडल को विस्तार देने की आवश्यकता है, ताकि वरिष्ठ नागरिक आत्मनिर्भर बनें, एक-दूसरे का सहयोग करें और अपने अनुभव से समाज व अर्थव्यवस्था में सार्थक योगदान दे सकें।

देश में जनगणना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। वर्तमान में प्रथम चरण के अंतर्गत आवासीय जनगणना की जा रही है। दूसरे चरण में प्रत्येक परिवार तथा बेघर व्यक्तियों की जनगणना होगी। इससे पहले नागरिकों को अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद जनगणना अधिकारी घर-घर जाकर विवरण का सत्यापन और आवश्यक जानकारी एकत्र करेंगे। जनगणना से प्राप्त आंकड़े देश की जनसंख्या, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का सही आकलन करने में सहायक होते हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सरकार विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाएं और कल्याणकारी नीतियां अधिक प्रभावी ढंग से तैयार करती है।

जनगणना से जुड़ी शुरुआती चर्चाओं के बीच एक महत्वपूर्ण चिंता देश की बदलती जनसांख्यिकीय संरचना को लेकर सामने आ रही है। भारत की कुल प्रजनन दर अब प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे पहुंच चुकी है, जिससे भविष्य में युवाओं की हिस्सेदारी घटने और बुजुर्ग आबादी बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। महानगरों में विवाह की बढ़ती उम्र, कम संतान की प्रवृत्ति तथा बदलती जीवनशैली भी इस परिवर्तन के प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। वहीं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जनगणना के आंकड़े देश की भावी सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या संबंधी नीतियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

चीन और जापान जैसे देशों ने वृद्ध होती आबादी की चुनौती का सामना किया है।

वहां वरिष्ठ नागरिक अनुभव और कौशल के आधार पर आज भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। भारत लंबे समय तक स्वयं को युवाओं का देश मानता रहा, लेकिन घटती प्रजनन दर और बढ़ती जीवन प्रत्याशा भविष्य में बुजुर्ग आबादी के बढ़ने का संकेत दे रही है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों को केवल आश्रित नहीं, बल्कि उत्पादक संसाधन के रूप में देखने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से देश में अनेक बुजुर्गों को पर्याप्त सम्मान, सामाजिक सुरक्षा और सुविधाएं नहीं मिल पातीं। परिवारों के विघटन और उपेक्षा की बढ़ती घटनाओं के बीच सरकार और समाज दोनों को वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की होगी।

इस दिशा में एक सकारात्मक पहल वर्ष 2004 में तमिलनाडु में सुनामी के बाद सामने आई। आर्थिक संकट के बावजूद अनेक वरिष्ठ नागरिकों ने हार मानने के बजाय स्वयं सहायता समूह (सेल्फ हेल्प ग्रुप) बनाकर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास शुरू किया। प्रारंभ में सरकारी स्तर पर पर्याप्त योजनाएं या प्रोत्साहन नहीं थे, फिर भी यह पहल लगातार आगे बढ़ती रही। आज यह अभियान तमिलनाडु से निकलकर कई राज्यों तक पहुंच चुका है। आज हजारों वरिष्ठ नागरिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इस मॉडल को विस्तार देने की आवश्यकता है, ताकि वरिष्ठ नागरिक आत्मनिर्भर बनें, एक-दूसरे का सहयोग करें और अपने अनुभव से समाज व अर्थव्यवस्था में सार्थक योगदान दे सकें। वरिष्ठ नागरिकों के स्वयं सहायता समूहों ने आत्मनिर्भरता की प्रेरक मिसाल पेश की है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन समूहों से जुड़े लगभग 70 प्रतिशत बुजुर्ग आर्थिक रूप से सशक्त बने हैं। नियमित छोटी बचत के आधार पर उन्होंने करोड़ों रुपये का सामूहिक कोष तैयार किया, जिससे जरूरतमंद सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराया गया और आय के नए अवसर भी विकसित हुए। बिहार के सुपौल जिले का यह मॉडल विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जहां कई बुजुर्ग आर्थिक रूप से सशक्त होकर सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। इस पहल की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा को भी प्रोत्साहन देना शुरू किया है। यह मॉडल आत्मनिर्भर और सम्मानजनक वृद्धावस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

वास्तविक समाधान तभी संभव है, जब प्रशासन, समाज और वरिष्ठ नागरिक मिलकर कार्य करें। बढ़ती उम्र के कारण भले ही बुजुर्ग शारीरिक रूप से पहले जैसे सक्रिय न रहें, लेकिन उनका अनुभव, ज्ञान और निर्णय क्षमता समाज की अमूल्य पूंजी है। उन्हें ऐसे कार्यों में अवसर दिए जाने चाहिए, जहां मार्गदर्शन, सलाह और अनुभव की आवश्यकता हो। युवा ऊर्जा और वरिष्ठों के अनुभव का समन्वय राष्ट्र निर्माण को नई दिशा दे सकता है। वरिष्ठ नागरिकों को केवल सहायता का पात्र नहीं, बल्कि विकास प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार बनाया जाना चाहिए। कुछ राज्यों में स्वयं सहायता समूहों की सफल पहल इसकी संभावना सिद्ध कर चुकी है। अब आवश्यकता है कि सरकार और समाज मिलकर इस मॉडल को व्यापक स्तर पर अपनाएं।

प्रेरणा

जिसकी जो कमी, वही सबसे बड़ी चाह

ज्ञान और धन—मानव जीवन के ये दोनों ऐसे आधार हैं जिनके बिना जीवन की पूर्णता की कल्पना करना कठिन है। धन जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जबकि ज्ञान जीवन को सही दिशा देता है। धन से सुख-सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सही निर्णय लेने की क्षमता केवल ज्ञान से ही आती है। दूसरी ओर, यदि ज्ञान तो हो लेकिन जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन न हों, तो व्यक्ति अनेक कठिनाइयों का सामना करता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि धन बड़ा है या ज्ञान, बल्कि यह है कि दोनों का संतुलन किस प्रकार जीवन को सार्थक बनाता है। स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग इसी सत्य को अत्यंत रोचक और तार्किक ढंग से सामने रखता है।

यह घटना उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद, जिन्हें उस समय नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से जाना जाता था, कॉलेज में अध्ययन कर रहे थे। उनकी प्रतिभा, तेज बुद्धि और तर्कशक्ति की चर्चा दूर-दूर तक होती थी। वे केवल पढ़ाई में ही उत्कृष्ट नहीं थे, बल्कि किसी भी विषय पर गहराई से विचार करने और तुरंत सटीक उत्तर देने की अद्भुत क्षमता रखते थे। उनके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास, विनम्रता और निर्भीकता का अद्भुत संगम था। यही गुण उन्हें अपने सहपाठियों से अलग बनाते थे।

कॉलेज में एक अंग्रेज प्रोफेसर थे, जिन्हें भारतीय छात्रों से विशेष लगाव नहीं था। वे अक्सर भारतीय विद्यार्थियों की योग्यता पर संदेह करते और अवसर मिलने पर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। नरेंद्र की प्रतिभा उन्हें सबसे अधिक खटकती थी। कक्षा में जब भी कोई कठिन प्रश्न पूछा जाता, नरेंद्र सहजता से उसका उत्तर दे देते। उनकी तार्किक सोच और स्पष्ट अभिव्यक्ति के कारण प्रोफेसर कई बार स्वयं निरुत्तर हो जाते थे। यही कारण था कि उनके मन में नरेंद्र के प्रति ईर्ष्या और बढ़ती चली गई। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि किसी ऐसे प्रश्न के माध्यम से नरेंद्र को पूरी कक्षा के सामने असमंजस में डाल देंगे, जिसका उत्तर देना आसान न हो। पूरी कक्षा शांत बैठी थी। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए नरेंद्र को खड़ा किया और कहा, "कल्पना करो कि तुम सड़क पर जा रहे हो। रास्ते में तुम्हें दो बैग मिलते हैं। एक बैग धन से भरा है और दूसरा ज्ञान से। तुम्हें दोनों में से केवल एक बैग उठाने का अवसर मिलता है। बताओ, तुम कौन-सा बैग उठाओगे?"

कक्षा के अधिकांश छात्रों को लगा कि नरेंद्र बिना सोचे-समझे ज्ञान वाला बैग चुनेंगे, क्योंकि ज्ञान का महत्व सभी जानते हैं। लेकिन नरेंद्र ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, "मैं धन वाला बैग उठाऊंगा।" उत्तर सुनते ही प्रोफेसर के चेहरे पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान फैल गई। उन्हें लगा कि अब नरेंद्र स्वयं अपने उत्तर से हास्यास्पद सिद्ध होंगे। उन्होंने हंसते हुए कहा, "मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। यदि मैं तुम्हारी जगह होता, तो मैं ज्ञान वाला बैग चुनता, क्योंकि ज्ञान धन से कहीं अधिक मूल्यवान है।"

पूरी कक्षा की निगाहें नरेंद्र पर टिक गईं। सभी जानना चाहते थे कि अब वे क्या कहेंगे। नरेंद्र ने पूरी शांति और विनम्रता के साथ मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, "सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति वही वस्तु लेना चाहता है, जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जिसके पास जिस चीज की कमी होती है, वह वही चुनता है। मेरे पास ज्ञान है, इसलिए मैंने धन वाला बैग चुना।"

यह उत्तर सुनते ही पूरी कक्षा तालियों से गूंज उठी। प्रोफेसर भी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। नरेंद्र ने न तो किसी का अपमान किया और न ही कटु शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने केवल एक वाक्य में ऐसा तर्क प्रस्तुत किया, जिसने प्रश्न पूछने वाले को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। यही सच्चे ज्ञान की पहचान है। ज्ञान केवल पुस्तकों में लिखे तथ्यों का संग्रह नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों को समझने और उचित समय पर उचित शब्दों का चयन करने की क्षमता भी ज्ञान का ही रूप है। यह प्रसंग हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है। अक्सर लोग धन और ज्ञान की तुलना करते हुए एक को श्रेष्ठ और दूसरे को कम महत्वपूर्ण मानने लगते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि दोनों का अपना-अपना महत्व है। ज्ञान के बिना धन का सही उपयोग नहीं हो सकता और धन के बिना कई बार ज्ञान का विस्तार भी कठिन हो जाता है। यदि किसी विद्वान के पास संसाधन ही न हों, तो उसकी प्रतिभा समाज तक पहुंचने में समय लग सकता है। वहीं यदि किसी व्यक्ति के पास अपार धन हो लेकिन विवेक न हो, तो वह धन उसके और समाज दोनों के लिए हानिकारक भी बन सकता है। स्वामी विवेकानंद का उत्तर केवल चतुराई नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास का भी परिचायक था। उन्हें अपने ज्ञान पर भरोसा था। जो व्यक्ति स्वयं की योग्यता को पहचानता है, वह किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं। वह दूसरों की बातों से प्रभावित होकर अपने निर्णय नहीं बदलता। आत्मविश्वास ही व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर बनाए रखता है।

आज के समय में भी यह घटना उतनी ही प्रासंगिक है। आधुनिक समाज में अधिकांश लोग धन कमाने की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ज्ञान, संस्कार और नैतिक मूल्यों को पीछे छोड़ देते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग केवल सैद्धांतिक ज्ञान को ही सब कुछ मान लेते हैं और व्यावहारिक जीवन की आवश्यकताओं की अनदेखी करते हैं। दोनों ही दृष्टिकोण अधूरे हैं। जीवन में सफलता तब मिलती है जब ज्ञान, विवेक, परिश्रम और आर्थिक समृद्धि एक-दूसरे के पूरक बनते हैं।

इस प्रसंग से यह शिक्षा भी मिलती है कि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसके उत्तर को सुनकर नहीं करना चाहिए। उसके उत्तर के पीछे छिपे विचार, अनुभव और दृष्टिकोण को समझना भी आवश्यक है। कई बार जो बात पहली नजर में साधारण या गलत प्रतीत होती है, वही गहराई से देखने पर असाधारण सत्य को उजागर कर देती है। नरेंद्र का उत्तर भी ऐसा ही था। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वास्तविक बुद्धिमत्ता वही है, जो परिस्थिति के अनुरूप तार्किक, संतुलित और सम्मानजनक उत्तर दे सके।

स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण जीवन इसी प्रकार की प्रेरणादायक घटनाओं से भरा हुआ है। उन्होंने बार-बार यह बताया कि ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास, विवेक और मानवता का विकास करना है। ऐसा ज्ञान ही व्यक्ति को महान बनाता है। जब ज्ञान के साथ विनम्रता और धन के साथ उदारता जुड़ जाती है, तब जीवन वास्तव में सफल और सार्थक बनता है।

यह घटना हमें याद दिलाती है कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति केवल धन नहीं और केवल ज्ञान भी नहीं, बल्कि दोनों का संतुलित उपयोग है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, वह धन अर्जित करने का मार्ग भी खोज लेता है, और जिसके पास धन है, उसे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए।

Border Trade में आया नया मोड़, Myanmar सीमा पर व्यापार शुरू, मगर घोषणा के बावजूद China सीमा पर ट्रेड शुरू नहीं हो पाया

कभी सीमाओं पर पसरा सन्नाटा कहानी का अंत लगता है, तो कभी वही खामोशी नए दौर की सबसे बड़ी दस्तक बन जाती है। सीमाएं जब खुलती हैं तो केवल रास्ते नहीं खुलते, बल्कि बाजारों में रौनक लौटती है, रोजी रोटी की उम्मीदें जागती हैं और सीमावर्ती बस्तियों की धड़कन फिर तेज हो जाती है। इस बार भी सीमाई व्यापार के मंच पर दो अलग अलग दृश्य सामने हैं। एक ओर भारत और म्यांमार के बीच छह वर्षों से बंद पड़ा व्यापारिक रास्ता फिर जीवन से भरने जा रहा है, जबकि दूसरी ओर लिपुलेख के रास्ते भारत और चीन के बीच व्यापार की पटकथा अभी अधूरी है। वहां बाजार तैयार नहीं होने से कारोबारी इंतजार की अगली कड़ी लिखने को मजबूर हैं। हम आपको बता दें कि भारत के सीमाई व्यापार मोर्चे पर एक साथ दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं। एक ओर भारत और म्यांमार के बीच पांगसाउ दर्रे से छह वर्ष बाद सीमाई व्यापार दोबारा शुरू होने जा रहा है, जिससे पूर्वोत्तर के सीमावर्ती इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से व्यापार सत्र शुरू होने के बावजूद भारतीय व्यापारियों को अभी भी नए बाजार की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि चीन की ओर से व्यापार व्यवस्था पूरी तरह तैयार नहीं होने के कारण कारोबार शुरू होने में देरी हो रही है। दोनों घटनाक्रम यह संकेत देते हैं कि सीमाई व्यापार केवल आर्थिक विषय नहीं, बल्कि कूटनीतिक, सामरिक और स्थानीय आजीविका से भी गहराई से जुड़ा हुआ है।

सबसे पहले भारत और म्यांमार के बीच व्यापार बहाली की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के पांगसाउ दर्रे से सीमाई व्यापार छह वर्षों के लंबे अंतराल के बाद फिर शुरू होने जा रहा है। यह व्यापार वर्ष 2019 में दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के कारण रोक दिया गया था। इसके बाद महामारी ने भी सीमाई आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियों को पूरी तरह ठप कर दिया। अब दोनों देशों के बीच सहमति बनने के बाद व्यापार दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार व्यापार जुलाई के अंत तक आरंभ होने की संभावना है।

इस व्यापार की सबसे बड़ी विशेषता मुक्त आवाजाही व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोग बिना औपचारिक अनुमति के दस किलोमीटर तक एक दूसरे के क्षेत्र में आ जा सकते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर व्यापार, छोटे कारोबार, सांस्कृतिक संपर्क और सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपनी जरूरत का सामान आसानी से उपलब्ध होगा और स्थानीय उत्पादों के लिए नया बाजार भी मिलेगा।

साथ ही पांगसाउ मार्ग के फिर खुलने से सबसे अधिक लाभ अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले और आसपास के इलाकों को मिलने की उम्मीद है। स्थानीय व्यापारिक संगठनों का कहना है कि पिछले छह वर्षों में व्यापार बंद रहने से छोटे व्यापारियों, परिवहन से जुड़े लोगों और स्थानीय बाजारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। सीमाई व्यापार फिर शुरू होने से रोजगार के नए अवसर बनेंगे, बाजारों में चहल पहल लौटेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिलेगा।

स्थानीय व्यापार संगठन के अध्यक्ष जोंगखाम मोरांग ने मीडिया से कहा कि व्यापार बहाल होने से क्षेत्र के हजारों छोटे व्यापारियों और आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि महामारी और व्यापार बंदी के दौरान जो आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह ठहर गई थीं, अब उनके फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद है। सीमा चौकी प्रत्येक महीने की दस, बीस और तीस तारीख को संचालित होगी, जिससे नियमित व्यापारिक गतिविधियां सुनिश्चित की जा सकेंगी।

दूसरी ओर उत्तराखंड स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार सत्र औपचारिक रूप से शुरू तो हो गया है, लेकिन वास्तविक कारोबार अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इसका कारण यह है कि चीन की ओर से नया बाजार और गोदाम पूरी तरह तैयार नहीं हो सके हैं। तिब्बत के तकलाकोट क्षेत्र में नया व्यापारिक केंद्र बनने का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते चीनी अधिकारियों ने भारतीय व्यापारियों से कुछ समय और प्रतीक्षा करने को कहा है।

हम आपको याद दिला दें कि लिपुलेख मार्ग से व्यापार वर्ष 2020 में गलवान घाटी की घटना के बाद रोक दिया गया था। इसके बाद लगातार चार वर्षों तक यह मार्ग बंद रहा। इस वर्ष व्यापार फिर शुरू होने की घोषणा से व्यापारियों में उत्साह तो बढ़ा, लेकिन बाजार तैयार नहीं होने के कारण उनकी उम्मीदों को फिलहाल झटका लगा है। व्यापारियों का कहना है कि यदि बाजार समय पर तैयार हो जाता तो इस बार खच्चरों की जगह सीधे मालवाहक वाहनों से सामान पहुंचाया जा सकता था। इसका सबसे बड़ा कारण धारचूला से लिपुलेख तक सड़क निर्माण का पूरा हो जाना है।

हालांकि भारतीय पक्ष ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। हम आपको बता दें कि व्यापार सत्र की औपचारिक शुरुआत जून में हो चुकी है और भारतीय व्यापारी जुलाई के शुरू में ही सीमा पार करने की तैयारी में थे। लेकिन इसी दौरान चीनी व्यापारिक साझेदारों की ओर से संदेश मिला कि नया बाजार और आवश्यक ढांचा अभी निर्माणाधीन है। इसलिए व्यापारियों को फिलहाल सीमा पार नहीं भेजा जाए। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद नई तिथि की सूचना देने का आश्वासन भी दिया गया है।

बहरहाल, दोनों घटनाएं इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि सीमाई व्यापार केवल वस्तुओं के आदान प्रदान तक सीमित नहीं है। यह सीमावर्ती क्षेत्रों की आजीविका, स्थानीय अर्थव्यवस्था, आधारभूत ढांचे और दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों से सीधे जुड़ा हुआ है।

अभियान

अमरनाथ की वह गुप्त कथा, जिसे सुनाने से पहले शिव ने छोड़ दिए नंदी, गणेश और स्वयं सृष्टि के पांच तत्व

सनातन धर्म की विशाल परंपरा में अनेक ऐसी कथाएं हैं, जो केवल धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि जीवन, मृत्यु, आत्मा और ब्रह्मांड के गहन रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। इन्हीं कथाओं में से एक है अमरनाथ की अमरकथा, जिसे हिंदू धर्म की सबसे रहस्यमयी और आध्यात्मिक घटनाओं में गिना जाता है। यह केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि उस ज्ञान का प्रतीक है, जिसे प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान शिव ने संसार से दूरी बनाई, अपने प्रियजनों को पीछे छोड़ा और ऐसी निर्जन गुफा का चयन किया, जहां उनके शब्दों का साक्षी कोई तीसरा न बन सके। हिमालय की बर्फीली वादियों में स्थित अमरनाथ गुफा आज करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन बहुत कम लोग उस कथा की गहराई को समझ पाते हैं, जिसने इस स्थान को सनातन संस्कृति के सबसे पवित्र तीर्थों में शामिल कर दिया। कहा जाता है कि एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के साथ विराजमान थीं। उनकी दृष्टि बार-बार भगवान शिव के गले में पड़ी मुंडमाला पर जा रही थी। यह माला साधारण नहीं थी। उसमें लगे प्रत्येक नरमुंड किसी रहस्य की ओर संकेत करते प्रतीत होते थे। माता पार्वती के मन में जिज्ञासा जागी और उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि वे इस माला को क्यों धारण करते हैं और इसके पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने बताया कि इस माला का प्रत्येक मुंड माता पार्वती के एक-एक जन्म का प्रतीक है। जब-जब उन्होंने नया जन्म लिया, तब-तब उस जन्म की स्मृति स्वरूप एक नया मुंड इस माला में जुड़ता गया। यह उत्तर सुनकर माता पार्वती चकित रह गईं। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें बार-बार जन्म लेना पड़ता है और मृत्यु का सामना करना पड़ता है, तो फिर भगवान शिव सदा अमर कैसे रहते हैं। आखिर वह कौन-सा ज्ञान है, जो उन्हें काल और मृत्यु से परे रखता है। माता पार्वती का यह प्रश्न केवल व्यक्तिगत जिज्ञासा नहीं था, बल्कि वह प्रश्न था जो युगों से मानव मन को विचलित करता आया है। जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों आती है और क्या वास्तव में अमरता संभव है? भगवान शिव जानते थे कि इस प्रश्न का उत्तर साधारण शब्दों में नहीं दिया जा सकता। यह सृष्टि के सबसे गूढ़ रहस्यों में से एक था। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि यदि वे वास्तव में अमरत्व का रहस्य जानना चाहती हैं, तो उन्हें एक ऐसी यात्रा पर चलना होगा जहां संसार का कोई अन्य जीव उनकी बातचीत का साक्षी न बने। इसके बाद दोनों कैलाश से निकल पड़े। यह यात्रा केवल एक गुफा तक पहुंचने की यात्रा नहीं थी, बल्कि मोह, माया, संबंध और भौतिक अस्तित्व से ऊपर उठने की यात्रा थी।

यात्रा के प्रथम पड़ाव पर भगवान शिव ने अपने प्रिय वाहन और अनन्य भक्त नंदी को छोड़ दिया। मान्यता है कि यही स्थान आगे चलकर पहलगाम कहलाया। नंदी केवल वाहन नहीं थे, वे अटूट श्रद्धा और समर्पण के प्रतीक थे। लेकिन अमरत्व के ज्ञान तक पहुंचने के लिए भगवान शिव ने यह संदेश दिया कि साधक को अपने सबसे प्रिय सहारे का भी त्याग करना पड़ता है। जब तक मनुष्य किसी बाहरी आधार पर निर्भर रहता है, तब तक वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान सकता।

इसके बाद भगवान शिव शेषनाग क्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने अपने गले में धारण किए हुए नागों को छोड़ दिया। हिंदू दर्शन में नाग केवल सर्प नहीं, बल्कि ऊर्जा, शक्ति और चेतना के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान शिव का यह त्याग दर्शाता है कि आध्यात्मिक यात्रा में शक्ति का अहंकार भी बाधा बन सकता है। जब तक व्यक्ति अपनी शक्तियों पर गर्व करता रहेगा, तब तक वह परम सत्य तक नहीं पहुंच पाएगा।

यात्रा आगे बढ़ी और भगवान शिव महागुण पर्वत पहुंचे। यहां उन्होंने अपने पुत्र भगवान गणेश को रोक दिया। यह प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान गणेश स्वयं बुद्धि, विवेक और ज्ञान के देवता हैं। फिर भी उन्हें अमरकथा सुनने की अनुमति नहीं मिली। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह बताया जाता है कि कुछ सत्य ऐसे होते हैं, जिन्हें केवल बौद्धिक क्षमता से नहीं समझा जा सकता। आत्मज्ञान अनुभव का विषय है, तर्क का नहीं। इसलिए भगवान शिव ने संकेत दिया कि परम सत्य को जानने के लिए मनुष्य को बुद्धि से भी आगे बढ़ना पड़ता है।

आगे बढ़ते हुए भगवान शिव पंचतरणी पहुंचे। यहां उन्होंने पंचमहाभूतों—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश—का त्याग किया। हिंदू दर्शन के अनुसार संपूर्ण शरीर इन्हीं पांच तत्वों से बना है। पंचतरणी में इन तत्वों का त्याग यह दर्शाता है कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप शरीर से परे है। जो स्वयं को केवल शरीर मानता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा रहता है। लेकिन जो आत्मा को पहचान लेता है, वह इन सीमाओं से मुक्त हो जाता है। जब भगवान शिव और माता पार्वती सभी सांसारिक बंधनों और प्रतीकों से मुक्त हो गए, तब वे उस निर्जन गुफा में पहुंचे जिसे आज अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है। गुफा के भीतर प्रवेश करने से पहले भगवान शिव ने यह सुनिश्चित करना चाहा कि वहां कोई अन्य जीवित प्राणी मौजूद न हो। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी योगशक्ति से कालाग्नि उत्पन्न की और उसे आदेश दिया कि वह गुफा के आसपास मौजूद प्रत्येक जीव को नष्ट कर दे। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने से पहले मनुष्य के भीतर मौजूद अज्ञान, मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार जैसी सभी प्रवृत्तियों का अंत होना आवश्यक है।

जब चारों ओर पूर्ण शांति स्थापित हो गई, तब भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरकथा सुनानी शुरू की। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि वे बीच-बीच में संकेत देती रहें ताकि उन्हें पता चलता रहे कि वे कथा सुन रही हैं। लेकिन कथा इतनी गहन और दिव्य थी कि माता पार्वती ध्यान की अवस्था में चली गईं और धीरे-धीरे उन्हें निद्रा आ गई।

संयोग से गुफा के एक कोने में कबूतरों का एक जोड़ा मौजूद था। कालाग्नि की ज्वाला से वे किसी प्रकार बच गए थे। जब माता पार्वती मौन हो गईं, तब वे कबूतर "हूं" जैसी ध्वनि निकालने लगे। भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं, इसलिए उन्होंने पूरी अमरकथा सुना दी। इस प्रकार वे कबूतर उस रहस्य के साक्षी बन गए, जिसे सुनने की अनुमति स्वयं गणेश और अन्य देवताओं को भी नहीं मिली थी। कथा समाप्त होने के बाद भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती तो निद्रा में थीं। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी कथा किसी और ने सुनी है। उन्होंने चारों ओर देखा और कबूतरों के उस जोड़े को पाया। पहले तो उन्हें आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उन्होंने इसे ईश्वरीय इच्छा मानकर उन कबूतरों को अमर होने का आशीर्वाद दे दिया। तभी से यह मान्यता प्रचलित है कि वह कबूतरों का जोड़ा आज भी अमरनाथ गुफा में निवास करता है। वर्षों से अनेक श्रद्धालु दावा करते रहे हैं कि उन्होंने अमरनाथ यात्रा के दौरान उन रहस्यमयी कबूतरों को देखा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतनी ऊंचाई और अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में कबूतरों का जीवित रहना असामान्य माना जाता है। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि भगवान शिव की अमरकथा के जीवित साक्षी हैं। यही कारण है कि उनके दर्शन को अत्यंत शुभ माना जाता है।

अमरनाथ की कथा केवल एक धार्मिक घटना नहीं है। इसके प्रत्येक पात्र और प्रत्येक पड़ाव के पीछे गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है। नंदी का त्याग बताता है कि आत्मज्ञान के मार्ग पर बाहरी सहारे छोड़ने पड़ते हैं। नागों का त्याग शक्ति के अहंकार से मुक्त होने का संकेत देता है। गणेश को पीछे छोड़ना यह सिखाता है कि केवल बुद्धि पर्याप्त नहीं है, अनुभव और साधना भी आवश्यक हैं। पंचतत्वों का त्याग शरीर की सीमाओं से ऊपर उठने का संदेश देता है और अंततः अमरनाथ गुफा यह बताती है कि आत्मा का सत्य संसार के शोर से दूर, भीतर की शांति में प्राप्त होता है।

अमरकथा का वास्तविक अर्थ शारीरिक अमरता नहीं है। सनातन धर्म कभी यह नहीं कहता कि शरीर हमेशा जीवित रह सकता है। अमरत्व का अर्थ है आत्मा की शाश्वतता को समझना। भगवान शिव ने माता पार्वती को यही बताया था कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। जो इस सत्य को जान लेता है, उसके लिए मृत्यु भय का विषय नहीं रह जाती।

आज भी जब लाखों श्रद्धालु कठिन पर्वतीय मार्गों से होकर अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं, तो वे केवल हिमलिंग के दर्शन नहीं करते, बल्कि उस महान संदेश को भी आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, जो भगवान शिव ने युगों पहले दिया था। यह संदेश है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानना है। जो अपने भीतर के शिवत्व को पहचान लेता है, वही वास्तविक अर्थों में अमर हो जाता है।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

नासिर नगर तोड़फोड़ विवाद में बड़ा खुलासा! निलंबित इंजीनियर ने हाईकोर्ट में नगर आयुक्त पर लगाए गंभीर आरोप, कहा-'वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर हुई कार्रवाई'

सूरत। नासिर नगर में हुई विवादित तोड़फोड़ की कार्रवाई अब कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर नया मोड़ ले चुकी है। इस मामले में निलंबित किए गए सूरत महानगरपालिका (एसएमसी) के कार्यकारी अभियंता सुजल प्रजापति ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अपने निलंबन को चुनौती दी है। याचिका में उन्होंने न केवल अपने निलंबन को नियमों के विरुद्ध बताया है, बल्कि सूरत नगर आयुक्त एम. नागराजन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि नासिर नगर में अतिक्रमण हटाने और तोड़फोड़ की कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों, विशेष रूप से नगर आयुक्त के निर्देश पर की गई थी, लेकिन बाद में पूरी जिम्मेदारी उन पर डालकर बिना विभागीय जांच के निलंबित कर दिया गया।

इस याचिका ने पूरे मामले को नया आयाम दे दिया है। अब तक प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा यह विवाद अब अदालत में नगर निगम की निर्णय प्रक्रिया, प्रशासनिक जवाबदेही और अधिकारों के प्रयोग जैसे महत्वपूर्ण सवालों के केंद्र में पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने भी प्रारंभिक सुनवाई के दौरान कुछ अहम टिप्पणियां करते हुए नगर आयुक्त से विस्तृत हलफनामा मांगा है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।

याचिका में सुजल प्रजापति ने सूरत नगर आयुक्त एम. नागराजन तथा सूरत महानगरपालिका को प्रतिवादी बनाया है। उन्होंने अदालत से मांग की है कि उनका निलंबन आदेश रद्द किया जाए क्योंकि यह सेवा नियमों के अनुरूप नहीं है। उनका कहना है कि नगर निगम के नियमों के अनुसार किसी कार्यकारी अभियंता को निलंबित करने का अधिकार स्थायी समिति के पास होता है, जबकि इस मामले में नगर आयुक्त ने स्वयं निलंबन आदेश जारी कर दिया। उनके अनुसार यह निर्णय अधिकार क्षेत्र से बाहर और कानूनी प्रक्रिया के विपरीत है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि 21 मई 2026 को उन्हें नगर आयुक्त के आधिकारिक मोबाइल नंबर से एक संदेश अग्रेषित किया गया था। उसी संदेश के आधार पर नासिर नगर क्षेत्र में कार्रवाई करने के निर्देश मिले थे। प्रजापति ने अदालत को बताया कि उन्होंने किसी व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर कार्रवाई नहीं की, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन किया। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि आवश्यकता हुई तो वे इस संबंध में शपथपत्र दाखिल करने के लिए भी तैयार हैं।

प्रजापति के अनुसार कार्रवाई वार्ड-7 स्थित चंद्रशेखर आजाद ब्रिज के निकट प्रस्तावित 60 फीट टीपी रोड के लिए रास्ता साफ करने तथा अतिक्रमण हटाने के उद्देश्य से की गई थी। उनका कहना है कि उन्हें स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि प्रस्तावित सड़क क्षेत्र में मौजूद अवरोधों को हटाया जाए ताकि परियोजना आगे बढ़ सके। उन्होंने अदालत में कहा कि एक सरकारी अधिकारी होने के नाते उन्होंने केवल अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन किया।

याचिका में सबसे गंभीर आरोप यह लगाया गया है कि नगर आयुक्त ने स्वयं कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन बाद में अदालत में यह कहा गया कि संबंधित तोड़फोड़ अधिकृत नहीं थी। प्रजापति का कहना है कि यह तथ्य वास्तविक घटनाक्रम से मेल नहीं खाता। उन्होंने दावा किया कि जांच समिति के समक्ष भी उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि पूरी कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर की गई थी, लेकिन उनकी बात पर उचित ध्यान नहीं दिया गया।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एसएमसी द्वारा गठित जांच समिति ने वास्तविक जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच करने के बजाय केवल यह पता लगाने का प्रयास किया कि कार्रवाई किस अधिकारी ने की। जबकि उनके अनुसार वास्तविक निर्णय और निर्देश उच्च स्तर से दिए गए थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि यदि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाती तो पूरी प्रशासनिक श्रृंखला सामने आ जाती।

अपनी दलीलों के समर्थन में सुजल प्रजापति ने अदालत के समक्ष कुछ चैट स्क्रीनशॉट भी प्रस्तुत किए हैं। उनका दावा है कि एसएमसी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नासिर नगर की तोड़फोड़ से संबंधित वीडियो और जानकारी साझा की गई थी। इतना ही नहीं, संबंधित अधिकारियों के आधिकारिक ग्रुप में भी इस कार्रवाई की जानकारी प्रसारित की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि निलंबन के बाद उन्हें उस आधिकारिक ग्रुप से हटा दिया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन पूरे मामले से दूरी बनाने का प्रयास कर रहा है।

याचिका में नासिर नगर के प्रभावित परिवारों का मुद्दा भी उठाया गया है। प्रजापति का कहना है कि 3 जून को प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए सर्वेक्षण कराने की मांग की गई थी। उनके अनुसार इस कार्रवाई से 59 मकान प्रभावित हुए थे, लेकिन प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को पहले पुनर्वास सुनिश्चित करना चाहिए था और उसके बाद आगे की कार्रवाई करनी चाहिए थी।

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त समय मांगा गया। सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि हाल ही में सूरत में आई बाढ़ और राहत कार्यों के कारण प्रशासन अत्यधिक व्यस्त रहा, इसलिए विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय की आवश्यकता है। हालांकि हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित संदेश नगर आयुक्त द्वारा याचिकाकर्ता को अग्रेषित किया गया था। अदालत ने इस संबंध में नगर आयुक्त को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अदालत में प्रस्तुत डिजिटल साक्ष्य और चैट रिकॉर्ड प्रमाणित हो जाते हैं तो मामले की दिशा बदल सकती है। यह केवल एक निलंबन का मामला नहीं रहेगा, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही, निर्णय प्रक्रिया और वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की भी न्यायिक जांच का विषय बन सकता है।

गौरतलब है कि नासिर नगर तोड़फोड़ का मामला पहले से ही व्यापक विवाद का विषय बना हुआ है। प्रभावित परिवारों, पुनर्वास, प्रशासनिक प्रक्रिया और कार्रवाई की वैधता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब निलंबित कार्यकारी अभियंता द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद यह विवाद और गहरा गया है।

हाईकोर्ट ने नासिर नगर तोड़फोड़ से संबंधित मुख्य याचिका पर 20 जुलाई को सुनवाई निर्धारित की है, जबकि कार्यकारी अभियंता सुजल प्रजापति की निलंबन संबंधी याचिका पर 21 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। अब सभी की नजर नगर आयुक्त द्वारा दाखिल किए जाने वाले हलफनामे और दोनों पक्षों की दलीलों पर टिकी है। अदालत में होने वाली आगामी सुनवाई न केवल निलंबन की वैधता, बल्कि पूरी तोड़फोड़ कार्रवाई की प्रशासनिक जिम्मेदारी और निर्णय प्रक्रिया पर भी महत्वपूर्ण असर डाल सकती है।

सूरत जिला माहेश्वरी सभा को मिला नया नेतृत्व, अतीन बाहेती अध्यक्ष और भगवती गग्गड़ सचिव निर्वाचित; समाजहित के नए संकल्प के साथ कार्यकाल की शुरुआत

सूरत। सूरत जिला माहेश्वरी सभा के वर्ष 2026–2029 कार्यकाल के लिए आयोजित अष्टम सत्र के चुनाव रविवार को शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गए। समाज के सदस्यों ने बड़ी संख्या में मतदान में भाग लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। चुनाव परिणाम घोषित होते ही सभा परिसर में उत्सव जैसा माहौल बन गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया तथा समाज के वरिष्ठजनों और सदस्यों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए नए कार्यकाल के लिए सफल नेतृत्व की कामना की।

सभा कार्यालय स्थित श्याम प्लाजा, सूरत में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक मतदान हुआ। निर्धारित समय के दौरान समाज के पात्र मतदाताओं ने अनुशासित ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण रही और मतदान के बाद मतगणना कर परिणामों की औपचारिक घोषणा की गई।

सभा के मीडिया प्रभारी सुनील माहेश्वरी ने चुनाव परिणामों की जानकारी देते हुए बताया कि टीम शिवांश के अतीन बाहेती अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। वहीं भगवती गग्गड़ को सभा का नया सचिव चुना गया। रामसहाय सोनी को कोषाध्यक्ष, मुरलीधर लाहोटी को संगठन मंत्री तथा महेश खटोड़ को प्रचार मंत्री के रूप में समाज ने अपना विश्वास सौंपा।

सभा की संगठनात्मक संरचना को मजबूत बनाने के उद्देश्य से तीनों संभागों के लिए उपाध्यक्षों का भी निर्वाचन किया गया। कैलाश संभाग से अशोक बाल्दी, महादेव संभाग से सत्यनारायण राठी तथा नीलकंठ संभाग से दीपक काबरा उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए। इसके अलावा सहसचिव पद पर दीपक डागा, कृष्णकांत तापड़िया और पवन चांडक ने जीत दर्ज की।

चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सभा परिसर में समाजजनों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। फूल-मालाओं से अभिनंदन करते हुए सभी ने नई कार्यकारिणी से समाज के विकास, संगठनात्मक एकता और सामाजिक गतिविधियों को नई दिशा देने की अपेक्षा व्यक्त की। वरिष्ठ सदस्यों ने विश्वास जताया कि नई टीम समाज की परंपराओं को आगे बढ़ाने के साथ-साथ युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और सामाजिक सेवा के नए आयाम स्थापित करने का कार्य करेगी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अतीन बाहेती ने अपनी जीत के बाद समाज के सभी मतदाताओं और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से महासभा के चुनाव पर्यवेक्षक सुरेश तोषनीवाल, मुख्य चुनाव अधिकारी लाल सारड़ा, चुनाव संचालन में सहयोग देने वाले महेंद्र झंवर तथा गोपाल भराड़िया सहित पूरी चुनाव टीम का धन्यवाद किया।

सरेआम पत्नी पर बरसाए मुक्के, सड़क पर घसीटकर की बेरहमी से पिटाई; सीसीटीवी वायरल होते ही पति गिरफ्तार, महिला मित्र पर भी केस

सूरत। मोटा वराछा क्षेत्र में दिनदहाड़े एक महिला के साथ हुई बर्बर मारपीट की घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया। बीच सड़क पर पति द्वारा पत्नी को बाल पकड़कर घसीटने, मुक्कों से हमला करने और सार्वजनिक रूप से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उतरन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर पूरे घटनाक्रम का पंचनामा भी कराया। मामले में आरोपी की महिला मित्र के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस घटना ने घरेलू विवादों के हिंसक रूप और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता हीरलबेन, जो अमरोली क्षेत्र की निवासी हैं, अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए एक ब्यूटी पार्लर संचालित करती हैं। उनका अपने पति प्रवीण गोलकिया के साथ वर्ष 2019 से पारिवारिक विवाद चल रहा है। दोनों पिछले कई वर्षों से अलग-अलग रह रहे हैं और उनके बीच वैवाहिक विवाद का मामला फिलहाल फैमिली कोर्ट में विचाराधीन है। प्रारंभिक जांच के अनुसार, शनिवार सुबह हीरलबेन अपनी बड़ी बेटी को गजेरा स्कूल छोड़कर एक्टिवा से घर लौट रही थीं। जब वह मोटा वराछा रोड स्थित प्रगति आईटी पार्क के समीप सड़क पार कर रही थीं, तभी अचानक एक सफेद रंग की अल्ट्रोज़ कार उनके सामने आकर रुकी। कार में उनके पति प्रवीण गोलकिया अपनी महिला मित्र के साथ मौजूद था।

आरोप है कि कार से उतरते ही प्रवीण गोलकिया ने पत्नी के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया और उसने महिला के सिर तथा पीठ पर लगातार मुक्कों से हमला करना शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपी ने इसके बाद महिला के बाल पकड़कर उसे सड़क पर घसीटा और बीच सड़क पर बेरहमी से मारपीट करता रहा। इस दौरान मौके पर मौजूद लोग पूरी घटना देखकर स्तब्ध रह गए। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि हमले के दौरान कार में मौजूद आरोपी की महिला मित्र भी बाहर आई और उसने भी मारपीट में हिस्सा लिया। महिला मित्र ने कथित रूप से पीड़िता को थप्पड़ मारे और हमला करने में आरोपी का साथ दिया। घटना के दौरान सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में राहगीर मौके पर एकत्र हो गए। स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर किसी तरह पीड़िता को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया।

शिकायत के अनुसार, घटनास्थल से जाते समय आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। मारपीट में घायल महिला को तत्काल 108 एम्बुलेंस की सहायता से स्मीमेर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्होंने उतरन पुलिस थाने में विस्तृत शिकायत दर्ज कराई। पूरी वारदात घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में भारी आक्रोश फैल गया।

बिहार में ट्रेन की खिड़की में मोबाइल चोर पकड़ा गया, पुलिस ने उसे 8-9 किलोमीटर तक लटकने के बाद पकड़ा

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। बिहार के एक स्टेशन पर खिड़की से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश कर रहे एक चोर को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ट्रेन चलने ही वाली थी कि मोबाइल चोर ने खिड़की से हाथ अंदर डाला। लेकिन खिड़की के पास बैठे यात्री सतर्क थे और जैसे ही उसका हाथ मोबाइल फोन तक पहुंचा, उन्होंने तुरंत उसे पकड़ लिया। चोर खिड़की के बाहर लटक गया और अंदर बैठे यात्रियों ने उसका हाथ पकड़ रखा था, तभी ट्रेन चलने लगी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें युवक खिड़की के बाहर लटका हुआ है। वह गिड़गिड़ा रहा है कि कृपया मेरा हाथ छोड़ दें, लेकिन यात्री उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। खगड़िया स्टेशन पर हुई इस घटना में बताया जा रहा है कि लोगों ने चोर को ट्रेन से लटकाकर करीब आठ-नौ किलोमीटर तक घसीटा। अंदर बैठे यात्रियों ने उसका वीडियो भी बनाया और उसमें उसका नाम और पता पूछा। चोर ने अपना नाम छोटू यादव और पिता का नाम पंकज यादव बताया। वह लखमिनिया गांव का रहने वाला था। उसने बचाव में कहा कि वह अपने किसी रिश्तेदार को ढूंढ रहा था। यात्रियों ने उसका हाथ तब तक पकड़े रखा जब तक वह पास के दूसरे स्टेशन पर नहीं पहुंच गया। यह घटना 9 जुलाई की रात को घटी। इसके बाद चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया।

बाढ़ से सबक: सूरत की पांचों खाड़ियों की होगी हाईटेक डिजिटल मैपिंग जीआईएस और सैटेलाइट तकनीक से तैयार होगा बाढ़ सुरक्षा का मास्टर प्लान

सूरत। हाल ही में आई भीषण बाढ़ ने सूरत की जल निकासी व्यवस्था और शहरी नियोजन को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर के अनेक इलाकों में जलभराव, बैकवाटर और खाड़ियों में पानी के प्राकृतिक प्रवाह में आई रुकावटों के बाद अब सूरत महानगरपालिका (एसएमसी) ने भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए व्यापक और तकनीक आधारित पहल शुरू की है। नगर निगम ने शहर की पांचों प्रमुख खाड़ियों का डिजिटल सर्वे और वैज्ञानिक स्कैनिंग शुरू कर दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत अत्याधुनिक जीआईएस (जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम), हाई-रिजॉल्यूशन सैटेलाइट इमेज और पुराने डिजिटल रिकॉर्ड की मदद से खाड़ियों की वर्तमान स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। इसके आधार पर एक हाईटेक डिजिटल डेटाबैंक तैयार होगा, जो भविष्य में बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी, अतिक्रमण हटाने और स्थायी इंजीनियरिंग सुधारों का आधार बनेगा।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना का उद्देश्य केवल खाड़ियों की मौजूदा स्थिति का नक्शा तैयार करना नहीं है, बल्कि पिछले दो दशकों में हुए भौगोलिक बदलावों, जल प्रवाह में आई रुकावटों और अनियोजित निर्माणों का वैज्ञानिक विश्लेषण करना भी है। प्रशासन का मानना है कि यदि खाड़ियों की वास्तविक स्थिति का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो जाता है तो भविष्य में बाढ़ जैसी आपदाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी और दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जा सकेंगी।

नगर निगम के पास वर्ष 2006 की विनाशकारी बाढ़ के बाद तैयार कराया गया लाइसेंस प्राप्त जीआईएस डेटा और वर्ष 2013 के आधिकारिक नक्शे पहले से उपलब्ध हैं। अब इन पुराने रिकॉर्ड की तुलना वर्ष 2026 के हाई-रिजॉल्यूशन सैटेलाइट मैप से की जा रही है। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि पिछले लगभग 20 वर्षों में खाड़ियों की चौड़ाई, गहराई, बहाव क्षेत्र और किनारों की संरचना में कितना परिवर्तन हुआ है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना की निगरानी स्वयं नगर आयुक्त के निर्देश पर की जा रही है। इसके लिए टाउन डेवलपमेंट ऑफिस (टीडीओ), टाउन प्लानिंग (टीपी), जीआईएस सेल, ड्रेनेज विभाग तथा नगर निगम के वरिष्ठ इंजीनियरों की संयुक्त टीम बनाई गई है। विशेषज्ञों की यह टीम पुराने डिजिटल रिकॉर्ड, भू-अभिलेखों और नवीनतम सैटेलाइट इमेज का मिलान कर प्रत्येक खाड़ी के हर हिस्से का वैज्ञानिक परीक्षण कर रही है। इसके लिए आधुनिक डिजिटल मैपिंग और डेटा विश्लेषण तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना न्यूनतम रहे।

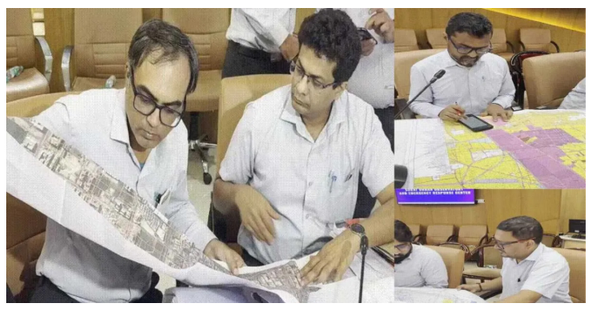

प्रारंभिक अध्ययन में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। अधिकारियों के अनुसार पिछले दो दशकों में कुछ स्थानों पर खाड़ियों का प्राकृतिक विस्तार हुआ है, जबकि अनेक क्षेत्रों में अतिक्रमण, अनियोजित निर्माण और अन्य गतिविधियों के कारण उनका प्राकृतिक मार्ग काफी संकरा हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यही संकरे हिस्से भारी वर्षा के दौरान पानी के प्राकृतिक बहाव में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शहर में जलभराव, बैकवाटर और बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं।

डिजिटल सर्वेक्षण के दौरान प्रत्येक खाड़ी के भीतर और किनारों पर बने सभी स्थायी एवं अस्थायी निर्माणों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इस डिजिटल डेटाबैंक में प्रत्येक निर्माण की स्थिति, क्षेत्रफल, स्वीकृति की स्थिति और जल निकासी पर उसके प्रभाव का अलग-अलग विवरण दर्ज किया जाएगा। तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से यह स्पष्ट किया जाएगा कि कौन-से निर्माण वैधानिक स्वीकृति के साथ किए गए हैं और कौन-से निर्माण अवैध रूप से खाड़ियों के क्षेत्र में विकसित किए गए हैं।

नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि जिन निर्माणों के कारण पानी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है और जल निकासी व्यवस्था प्रभावित हो रही है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि डिजिटल सर्वे में ऐसे अतिक्रमण सामने आते हैं जो बाढ़ की स्थिति को गंभीर बनाते हैं, तो उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।

हालांकि नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यह परियोजना केवल अवैध अतिक्रमणों की पहचान तक सीमित नहीं रहेगी। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर विशेषज्ञ यह भी तय करेंगे कि किन क्षेत्रों में रिटेनिंग वॉल, अतिरिक्त ड्रेनेज चैनल, आधुनिक हाइड्रोलिक संरचनाएं, जल निकासी क्षमता बढ़ाने वाले इंजीनियरिंग कार्य अथवा अन्य स्थायी समाधान विकसित किए जाने आवश्यक हैं। आवश्यकता पड़ने पर खाड़ियों के प्राकृतिक प्रवाह को पुनर्स्थापित करने तथा उनकी भौगोलिक संरचना में तकनीकी सुधार करने की भी योजना बनाई जा सकती है।

नगर निगम का मानना है कि पारंपरिक सर्वेक्षण पद्धति की तुलना में आधुनिक जीआईएस, सैटेलाइट इमेजिंग और डिजिटल मैपिंग तकनीक कहीं अधिक सटीक और विश्वसनीय परिणाम प्रदान करती है। इससे न केवल वास्तविक स्थिति का वैज्ञानिक आकलन संभव होगा, बल्कि भविष्य में शहरी नियोजन, जल निकासी परियोजनाओं और आपदा प्रबंधन के लिए भी एक स्थायी डिजिटल आधार उपलब्ध होगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि तेजी से फैलते शहरीकरण के कारण खाड़ियों, नालों और प्राकृतिक जलमार्गों पर बढ़ते दबाव ने कई शहरों में बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। ऐसे में सूरत द्वारा अपनाई जा रही यह तकनीक-आधारित पहल अन्य नगर निकायों के लिए भी एक मॉडल साबित हो सकती है। यदि इस परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो भविष्य में भारी बारिश के दौरान जलभराव की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा।

नगर निगम का कहना है कि लगभग 20 वर्ष पुराने डिजिटल रिकॉर्ड और नवीनतम हाई-रिजॉल्यूशन सैटेलाइट तकनीक के समन्वय से तैयार होने वाला यह व्यापक डिजिटल ब्लूप्रिंट आने वाले वर्षों में सूरत के शहरी विकास और बाढ़ प्रबंधन की दिशा तय करेगा। प्रशासन को उम्मीद है कि इस वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर लिए जाने वाले निर्णय शहर को प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक सुरक्षित, सुनियोजित और सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

नए मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 में माता-पिता के एसआईआर विवरण प्रदान करना अनिवार्य है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के इच्छुक नए आवेदकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, अब से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 जमा करने के साथ-साथ आवेदकों को अपने माता-पिता के "विशेष गहन पुनरावलोकन" (यानी एसआईआर) का विवरण देना अनिवार्य होगा।

दिलचस्प बात यह है कि इस नए प्रावधान के लिए मुख्य वैधानिक प्रपत्र-6 में कोई संशोधन नहीं किया गया है। लेकिन यह घोषणा प्रशासनिक निर्देशों के माध्यम से जोड़ी गई है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर प्रपत्र-6 भरता है, तो जब तक वह इस नई घोषणा के कॉलम में माता-पिता के एसआईआर विवरण नहीं भरता, तब तक आवेदन प्रक्रिया सिस्टम में आगे नहीं बढ़ेगी।

पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम समेत कई इलाकों में अल्पसंख्यक वोटों को बड़े पैमाने पर हटाए जाने के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि ये आरोप निराधार हैं। सभी मतदाताओं को मतदाता सूची से अपना नाम हटाए जाने को चुनौती देने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। इतना ही नहीं, अब इस नए नियम से पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं के लिए माता-पिता के पुराने चुनावी रिकॉर्ड खोजने की प्रक्रिया और भी बढ़ जाएगी।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पोरबंदर स्टेशन पर चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन

अमृत भारत स्टेशन योजना (ABSS) के अंतर्गत पोरबंदर रेलवे स्टेशन पर विद्यार्थियों में रचनात्मकता एवं जन-जागरूकता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 13 जुलाई को चित्रकला (Drawing) एवं निबंध (Essay) प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री हुबलाल जगन के नेतृत्व एवं देखरेख में आयोजित किया गया।

पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि प्रतियोगिताओं में पोरबंदर के पांच प्रतिष्ठित विद्यालयों—महारानी श्रीमती रूपालीबा विद्यालय, नवयुग विद्यालय, बालूबा कन्या विद्यालय, के. बी. जोशी कन्या विद्यालय तथा भावसिंहजी सरकारी हाई स्कूल—के लगभग 800 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा, कल्पनाशीलता एवं अभिव्यक्ति कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

उन्होंने बताया कि प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में अमृत भारत स्टेशन योजना, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण तथा भारतीय रेल के विकास एवं आधुनिकीकरण के प्रति जागरूकता विकसित करना था। प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत चित्रों एवं निबंधों में नवीन सोच, सामाजिक संदेश तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ।

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों तथा विजेताओं को वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से होने वाले पोरबंदर स्टेशन के लोकार्पण समारोह में 17 जुलाई को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रतिभागियों को प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति-चिह्न प्रदान किए जाएंगे।

पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की सफलता में सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों का सराहनीय योगदान रहा। मंडल प्रशासन ने सभी प्रतिभागियों को उनकी उत्कृष्ट सहभागिता के लिए बधाई देते हुए भविष्य में भी ऐसे रचनात्मक, शैक्षणिक एवं जन-जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।

गुजरात के दो प्रमुख कृषि उत्पादों को मिली वैश्विक पहचान, ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को मिला प्रतिष्ठित GI टैग

- GI टैग प्राप्त उत्पादों को सामान्य उत्पादों की तुलना में 20-30 प्रतिशत तक अधिक बाजार मूल्य मिलने की संभावना
- GI टैग से ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को मिलेगी आधिकारिक भौगोलिक पहचान, बढ़ेगी वैश्विक बाजार में विश्वसनीयता और निर्यात की संभावनाएं
- किसानों, उत्पादकों और पारंपरिक कृषि विरासत को मिलेगा कानूनी संरक्षण तथा कृषि आधारित उद्यमों को नए अवसर

गांधीनगर, 13 जुलाई : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' और 'लोकल टू ग्लोबल' के विज़न को साकार करते हुए तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात अपने पारंपरिक कृषि उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इसी क्रम में उत्तर गुजरात के प्रसिद्ध मसाला उत्पाद ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को भारत सरकार की जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) रजिस्ट्री द्वारा प्रतिष्ठित GI टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही दोनों उत्पाद अब वैश्विक बाजार में अपनी विशिष्ट भौगोलिक पहचान और आधिकारिक ब्रांड के रूप में स्थापित होंगे।

गुजरात की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा, "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' और 'लोकल टू ग्लोबल' के विज़न के अनुरूप ऊंझा के जीरा और सौंफ को मिला GI टैग 'गांव से ग्लोबल' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह केवल एक सरकारी प्रमाणन नहीं है बल्कि हमारे किसानों की अथक मेहनत, गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादन, व्यापारियों के विश्वास और ऊंझा की समृद्ध कृषि परंपरा का सम्मान है। इससे दोनों उत्पादों को विश्व बाजार में विशिष्ट पहचान मिलेगी, वे अपनी अलग ब्रांड के रूप में स्थापित होंगे और गुजरात के कृषि उत्पादों की वैश्विक प्रतिष्ठा को नई मजबूती मिलेगी।"

GI टैग गुणवत्ता, प्रामाणिकता और भौगोलिक पहचान की आधिकारिक मुहर

GI (भौगोलिक संकेतक) टैग ऐसे उत्पादों को प्रदान किया जाता है, जिनकी विशिष्ट गुणवत्ता, प्रतिष्ठा अथवा विशेषताएं किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी होती हैं। यह टैग वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। GI टैग संबंधित उत्पाद की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है, निर्धारित गुणवत्ता मानकों की रक्षा करता है तथा नकली उत्पादों पर प्रभावी रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

GI टैग से बढ़ेगी ब्रांड वैल्यू और निर्यात क्षमता

GI टैग मिलने के बाद ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ दोनों प्रमाणित भौगोलिक ब्रांड के रूप में स्थापित होंगे। इससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी तथा बेहतर मूल्य और निर्यात की संभावनाएं मजबूत होंगी। विशेषज्ञों के अनुसार GI टैग प्राप्त उत्पाद सामान्य उत्पादों की तुलना में 20 से 30 प्रतिशत तक अधिक बाजार मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इससे किसानों की आय में वृद्धि के साथ स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की संभावना है।

सामूहिक प्रयासों से मिला ऊंझा जीरा और ऊंझा वरीयाली को GI टैग

ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को GI टैग दिलाने की प्रक्रिया विभिन्न संस्थाओं के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। इस उपलब्धि में खेतीवाड़ी उत्पन्न बाजार समिति (APMC), ऊंझा, भारत सरकार, गुजरात सरकार के बागायत एवं किसान कल्याण विभाग, सरदारकृषिनगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय (SDAU) तथा भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (EDII), गुजरात सहित विभिन्न संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उपलब्धि किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, व्यापारियों और विभिन्न संस्थाओं के सफल समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है।

इस विशेष उपलब्धि पर ऊंझा कृषि उपज मंडी समिति (APMC) के चेयरमैन श्री दिनेश पटेल ने कहा, "ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को मिला GI टैग ऊंझा के किसानों और मसाला व्यापार के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। इससे दोनों उत्पादों की प्रामाणिकता और बाजार विश्वसनीयता को नई मजबूती मिलेगी। वैश्विक स्तर पर इनकी मांग और स्वीकार्यता बढ़ेगी, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलने के साथ निर्यात और मूल्य संवर्धन के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।"

भारत की GI सूची में सशक्त हो रही गुजरात की कृषि पहचान

वर्तमान में भारत सरकार की GI रजिस्ट्री में 400 से अधिक उत्पाद पंजीकृत हैं, जिनमें गुजरात के गिर केसर आम, भालिया गेहूं, कच्छी खारेक और अमलसाड़ी चीकू जैसे विशिष्ट कृषि उत्पादों शामिल हैं। अब ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ के भी इस सूची में शामिल होने से गुजरात के GI टैग प्राप्त कृषि उत्पादों की श्रृंखला और सशक्त हुई है। इससे राज्य के कृषि उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को नई मजबूती मिलने के साथ किसानों के लिए बेहतर बाजार, मूल्य संवर्धन और निर्यात के अवसर भी बढ़ेंगे।

मंडल रेल प्रबंधक ने धोला-पोरबंदर रेलखंड एवं पोरबंदर स्टेशन का किया विस्तृत संरक्षा निरीक्षण

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) श्री दिनेश वर्मा ने 11 जुलाई को धोला–पोरबंदर रेलखंड का विस्तृत संरक्षा निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेलखंड में संरक्षा व्यवस्था, संरक्षा संबंधी कार्यों की प्रगति, यात्री सुविधाओं, ट्रैक, सिग्नल एवं दूरसंचार प्रणाली सहित विभिन्न रेल परिसंपत्तियों का गहन निरीक्षण किया गया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि निरीक्षण के उपरांत मंडल रेल प्रबंधक ने पोरबंदर रेलवे स्टेशन का भी विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान स्टेशन पर हाल ही में पूर्ण हुए यार्ड रीमॉडलिंग कार्यों का सूक्ष्म परीक्षण किया गया। उन्होंने नई यार्ड व्यवस्था, परिचालन क्षमता में हुए सुधार, संरक्षा मानकों के अनुपालन तथा कार्य की गुणवत्ता का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को इन परिसंपत्तियों के प्रभावी अनुरक्षण एवं सुरक्षित संचालन

सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मंडल रेल प्रबंधक ने अमृत स्टेशन के तहत पुनर्विकसित पोरबंदर रेलवे स्टेशन के पूर्ण किए गए कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने यात्री सुविधाओं, स्वच्छता, संरक्षा, सुरक्षा एवं समन्वय से जुड़े विभिन्न पहलुओं का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं गुणवत्तापूर्ण रेल सेवाएँ उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि संरक्षा से संबंधित सभी विकास एवं अनुरक्षण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूर्ण किए जाएँ तथा रेलवे परिसंपत्तियों के रखरखाव एवं सुरक्षित संचालन में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।

इस अवसर पर मंडल के शाखाधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित रहे।

वडोदरा मंडल की सराहनीय पहल, रेल सहायकों को नयी वर्दी का वितरण

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा अपने फ्रंटलाइन कर्मचारियों के कल्याण एवं यात्री सुविधा को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत वडोदरा रेलवे स्टेशन पर कार्यरत कुलियों (सहायकों) को नई वर्दियों का वितरण किया।

वडोदरा मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री नरेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके द्वारा स्टेशन पर कार्यरत 70 रेल सहायकों को वर्दी के सेट वितरित किए। प्रत्येक रेल सहायक को कुल चार शर्टों का एक सेट प्रदान किया गया, जिसमें गर्मियों के लिए तीन लाल शर्टें तथा सर्दियों के लिए एक शर्ट शामिल है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री नरेन्द्र कुमार ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य कुलियों को एक समान एवं सुव्यवस्थित पहचान प्रदान करना, उनके सम्मान एवं आत्मविश्वास को बढ़ावा देना तथा यात्रियों के लिए उन्हें आसानी से पहचानने योग्य बनाना है। इससे यात्रियों को आवश्यक सहायता प्राप्त करने में सुविधा होगी तथा स्टेशन पर सेवा की गुणवत्ता में भी सकारात्मक सुधार होगा।

वडोदरा मंडल पश्चिम रेलवे अपने कर्मचारियों के कल्याण तथा यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं बेहतर सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है तथा भविष्य में भी ऐसे जनकल्याणकारी एवं कर्मचारी हितैषी प्रयास करता रहेगा।

गुजरात में आपदा के विरुद्ध नागरिकों को सहायक होने के लिए 'युवा आपदा मित्र स्कीम' अंतर्गत 4,526 युवा प्रशिक्षित

- राज्य के 17 जिलों में 'आपदा मित्रों' को अत्याधुनिक इमर्जेंसी किट से किया गया सज्ज
- जन भागदारी से आपदा प्रबंधन : गुजरात में 50 प्रतिशत महिला भागीदारी के साथ तैयार हो रही है 'आपदा मित्र' की नई पीढ़ी
- आपदा मित्र की सामाजिक सुरक्षा के लिए तीन वर्ष तक 5 साथ रुपए का बीमा कवच

गांधीनगर : गुजरात सरकार द्वारा प्राकृतिक एवं मानस सृजति आपदाओं के विरुद्ध नागरिकों की सुरक्षा अधिक सुनिश्चित करने के लिए 'आपदा मित्र' प्रोजेक्ट को अधिक वेग दिया गया है। केन्द्र सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा वर्ष 2016 में भरूच जिले से केवल 200 आपदा मित्रों के साथ शुरू हुई यह योजना हाल में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में वटवृक्ष बनकर गाँवों-शहरों में आपदा के समय सेवा दे रही है। हाल में कार्यरत 'युवा आपदा मित्र स्कीम' अंतर्गत राज्य के 17 जिलों के लिए एनसीसी, एनएसएस, एमवाईबी, बीएसएंडजी के कुल 11,850 स्वयंसेवकों के लक्ष्य के सामने पहले चरण में अब तक लगभग 4,526 युवाओं को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया है। इस योजनांतर्गत आपदा प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए उनकी 50 प्रतिशत भागीदारी का विशेष लक्ष्य रखा गया है।

गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जीएसडीएमए)-गांधीनगर की विज्ञप्ति में उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया गया कि आपदा मित्र सामाजिक स्तर पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के स्थानीय स्वयंसेवकों का समूह है, जो आपदा के समय तत्काल बाचव कार्य करता है। पूर्व में 'अप स्केलिंग ऑफ आपदा मित्र स्कीम' अंतर्गत 17 जिलों के 5,500 आपदा मित्रों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल

(एसडीआरएफ) के माध्यम से 12 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया, जबकि वर्तमान योजना में पहले चरण में एसडीआरएफ तथा मास्टर ट्रेनर्स द्वारा 7 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है और अन्य दूसरे चरण में स्पीपा के माध्यम से एडवांस प्रशिक्षण का आयोजन है। इन 17 जिलों में अहमदाबाद, अमरेली, आणंद, भावनगर, जामनगर, जूनागढ, खेडा, कच्छ, मोरबी, नर्मदा, नवसारी, पोरबंदर, राजकोट, सूरत, तापी, वडोदरा और वलसाड जिलों को शामिल किया गया है।

बचाव कार्य को अधिक सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षित आपदा मित्रों को 10 हजार रुपए मूल्य की इमर्जेंसी रिस्पॉण्डर किट (ईआरके) दी जाती है। इस किट में लाइफ जैकेट, सलर टॉर्च, फर्स्ट एड किट, हेलमेट तथा 50 मीटर लंबा डिफेंस क्वालिटी रस्सा जैसे 15 अनिवार्य वस्तुएँ शामिल हैं। इसके अलावा; जिला स्तर पर आपदा के समय बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाने के लिए 19 लाख रुपए मूल्य की ईईईआर किट भी रिजर्व रखी जाती है, जिसमें अद्यतन इनफ्लेटेबल रेस्क्यू बोट, चेन सॉ मशीन, सैटेलाइट जीपीएस तथा वॉकी-टॉकी जैसे संसाधन-उपकरण होते हैं। आपदा मित्र के प्रशिक्षण के निश्चित मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इनमें उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें पूर्व सैनिक, सेवानिवृत्त चिकित्सा व्यवसायियों तथा सिविल इंजीनियरों के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है। उम्मीदवार सम्बद्ध जिले का निवासी होना चाहिए और उसने कम से कम कक्षा 7 उत्तीर्ण की होनी चाहिए।

प्रोत्साहन के हिस्से के रूप में इस प्रशिक्षण के बाद आपदा मित्र को प्रमाणपत्र, परिचय पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए तीन वर्ष तक 5 लाख रुपए का बीमा कवच भी दिया जाता है।

पूर्व में कोविड-19 महामारी तथा वर्ष 2020 में भारी बाढ़ में भरूच जिले के आपदा मित्रों ने प्रशासन के साथ मिलकर प्रशंसनीय जनसेवा की थी। किसी भी आपदा के समय आम नागरिक या प्रशासन जिला स्तरीय डिस्ट्रिक्ट इमर्जेंसी ऑपरेशन सेंटर (डीईओसी) का संपर्क कर आपदा मित्रों की तत्काल सहायता प्राप्त कर सकता है।

विज्ञप्ति में कहा गया कि जिला स्तरीय डीईओसी द्वारा आपदा मित्रों की संपूर्ण संपर्क सूची मैंटेन की जाती है। किसी भी आपदा के समय इस केन्द्र द्वारा आपदा मित्रों का संपर्क कर तत्काल उनकी सहायता ली जाती है।

यात्रियों की सुविधा हेतु प्रयागराज–गांधीनगर कैपिटल द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के अतिरिक्त 13 फेरे

यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ एवं उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने गाड़ी संख्या 04111/04112 प्रयागराज–गांधीनगर कैपिटल–प्रयागराज द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के संचालन अवधि का विस्तार करते हुए अतिरिक्त 13 फेरे चलाने का निर्णय लिया है।

पश्चिम रेलवे भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार, गाड़ी संख्या 04111 प्रयागराज–गांधीनगर कैपिटल स्पेशल दिनांक 18 जुलाई से 29 अगस्त तक प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को कुल 13 फेरों के लिए संचालित की जाएगी।

इसी प्रकार, गाड़ी संख्या 04112 गांधीनगर कैपिटल–प्रयागराज स्पेशल दिनांक 19 जुलाई से 30 अगस्त तक प्रत्येक बुधवार एवं रविवार को कुल 13 फेरों के लिए संचालित होगी।

इस विशेष ट्रेन का मार्ग, समय-सारिणी, ठहराव, रेक संरचना, कोच संयोजन तथा अन्य सभी परिचालन संबंधी व्यवस्थाएं पूर्ववत यथावत रहेंगी। ट्रेन दोनों दिशाओं में चांदखेड़ा रोड, मेहसाणा जंक्शन, पालनपुर जंक्शन, आबू रोड, सुमेरपुर जवाई

बांध, फालना, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर जंक्शन, किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, ईदगाह, टूण्डला जंक्शन, इटावा जंक्शन, गोविंदपुरी तथा फतेहपुर स्टेशनों पर ठहरेगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा से पूर्व अपनी आरक्षण स्थिति एवं ट्रेन की समय-सारिणी की जानकारी प्राप्त कर लें। इन अतिरिक्त फेरों के लिए बुकिंग प्रारंभ हो चुकी है।

ट्रेन के समय, ठहराव एवं अन्य विस्तृत जानकारी के लिए यात्री राष्ट्रीय रेल पूछताछ प्रणाली (NTES), अधिकृत वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in तथा IRCTC के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे की डाइविंग टीम ने 79वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप-2026 में जीते 11 पदक

चेन्नई में आयोजित 79वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप-2026 में पश्चिम रेलवे की डाइविंग टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 11 पदक जीतकर पश्चिम रेलवे का गौरव बढ़ाया। टीम ने प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, 2 रजत तथा 6 कांस्य पदक अपने नाम किए।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पलक शर्मा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल चार पदक जीते। उन्होंने महिला प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत, महिला प्लेटफॉर्म सिंक्रोनाइज्ड तथा महिला 3 मीटर स्प्रिंगबोर्ड सिंक्रोनाइज्ड स्पर्धाओं में तीन स्वर्ण पदक, जबकि महिला 1 मीटर स्प्रिंगबोर्ड स्पर्धा में एक रजत पदक अर्जित किया। ह्रतिका श्रीराम ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल पाँच पदक अपने नाम किए। उन्होंने महिला प्लेटफॉर्म सिंक्रोनाइज्ड तथा महिला 3 मीटर स्प्रिंगबोर्ड सिंक्रोनाइज्ड स्पर्धाओं में दो स्वर्ण पदक तथा महिला प्लेटफॉर्म, महिला 3 मीटर स्प्रिंगबोर्ड और महिला 1 मीटर स्प्रिंगबोर्ड स्पर्धाओं में तीन कांस्य पदक जीते।

पुरुष वर्ग में अभिषेक यू ने पुरुष 1 मीटर स्प्रिंगबोर्ड स्पर्धा में एक रजत पदक तथा पुरुष 3 मीटर स्प्रिंगबोर्ड एवं पुरुष 3 मीटर

स्प्रिंगबोर्ड सिंक्रोनाइज्ड स्पर्धाओं में दो कांस्य पदक जीते। वहीं, निहाल गिराम ने पुरुष प्लेटफॉर्म सिंक्रोनाइज्ड स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर पश्चिम रेलवे के पदकों की संख्या में एक और उपलब्धि जोड़ी।

पश्चिम रेलवे सभी पदक विजेताओं को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देती है तथा नेशनल चैंपियनशिप में उनके समर्पण, कठिन परिश्रम और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संपूर्ण डाइविंग टीम की सराहना करती है।

14 एवं 15 जुलाई, 2026 को केलवे रोड स्टेशन पर नॉन-इंटरलॉकिंग ब्लॉक,इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एवं कवच प्रणाली के कार्य के कारण ट्रेन सेवाएं प्रभावित

विरार–दहानू रोड (चरण-I) चौथी लाइन परियोजना के अंतर्गत केलवे रोड स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (EI) प्रणाली एवं कवच के कमीशनिंग कार्य को सुगम बनाने के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा 14 एवं 15 जुलाई, 2026 को केलवे रोड स्टेशन पर प्री-नॉन-इंटरलॉकिंग (Pre-NI) तथा नॉन-इंटरलॉकिंग (NI) ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्री-नॉन-इंटरलॉकिंग ब्लॉक मंगलवार, 14 जुलाई, 2026 को 16.00 बजे से 17.30 बजे तक लिया जाएगा। इस दौरान केलवे रोड स्टेशन पर सिग्नलिंग उपकरणों की पूर्व व्यवस्था, प्वाइंट वायरिंग में संशोधन तथा अन्य संबंधित सिग्नलिंग कार्य किए जाएंगे। इसके पश्चात बुधवार, 15 जुलाई, 2026 को 08.10 बजे से 11.10 बजे तक नॉन-इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया जाएगा, जिसके दौरान केलवे रोड स्टेशन पर नई इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एवं कवच प्रणाली का कमीशनिंग कार्य किया जाएगा।

ब्लॉक अवधि के दौरान कुछ उपनगरीय ट्रेन सेवाएं पूर्णतः निरस्त रहेंगी, जबकि कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट तथा शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त

कुछ मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन भी रेगुलेट किया जाएगा।

15 जुलाई, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली निरस्त ट्रेनें:

1. बोईसर से 08:35 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 61001 बोईसर–वसई रोड मेमू निरस्त रहेगी।
2. दहानू रोड से 09:37 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 93012 दहानू रोड–विरार लोकल निरस्त रहेगी।
3. दहानू रोड से 10:22 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 93014 दहानू रोड–विरार लोकल निरस्त रहेगी।
4. विरार से 09:30 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 93013 विरार–दहानू रोड लोकल निरस्त रहेगी।
5. चर्चगेट से 08:49 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 93015 चर्चगेट–दहानू रोड लोकल निरस्त रहेगी।

14 जुलाई, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली रेगुलेट होने वाली ट्रेनें:

1. ट्रेन संख्या 22961 मुंबई सेंट्रल–अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस 25 मिनट रेगुलेट होगी।
2. ट्रेन संख्या 82901 मुंबई सेंट्रल–अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस 25 मिनट रेगुलेट होगी।
3. ट्रेन संख्या 12954 हजरत निजामुद्दीन–मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस 30 मिनट रेगुलेट होगी।
4. ट्रेन संख्या 20932 इंदौर–तिरुवनंतपुरम नॉर्थ एक्सप्रेस 1 घंटा 45 मिनट रेगुलेट होगी।
5. ट्रेन संख्या 22956 भुज–बांद्रा टर्मिनस कच्छ एक्सप्रेस 1 घंटा 50 मिनट रेगुलेट होगी।
6. ट्रेन संख्या 12479 जोधपुर–बांद्रा टर्मिनस सूर्यनगरी एक्सप्रेस 1 घंटा 30 मिनट रेगुलेट होगी।
7. ट्रेन संख्या 12489 श्रीगंगानगर–दादर एक्सप्रेस 30 मिनट रेगुलेट होगी।

15 जुलाई, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली रेगुलेट होने वाली ट्रेनें:

1. दहानू रोड से 07:17 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 93202 दहानू रोड–चर्चगेट लोकल 25 मिनट रेगुलेट होगी।
2. ट्रेन संख्या 12922 सूरत–मुंबई सेंट्रल फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस 25 मिनट रेगुलेट होगी।
3. दहानू रोड से 08:35 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 93010 दहानू रोड–बोरीवली लोकल 25 मिनट रेगुलेट होगी।
4. ट्रेन संख्या 22962 अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस 1 घंटा रेगुलेट होगी।
5. ट्रेन संख्या 12934 अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल कर्णावती एक्सप्रेस 40 मिनट रेगुलेट होगी।
6. ट्रेन संख्या 12932 अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस 30 मिनट रेगुलेट होगी।
7. ट्रेन संख्या 82902 अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस 25 मिनट रेगुलेट होगी।
8. ट्रेन संख्या 69139 बोरीवली–वलसाड मेमू 25 मिनट रेगुलेट होगी।
9. चर्चगेट से 07:11 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 93009 चर्चगेट–दहानू रोड लोकल 25 मिनट रेगुलेट होगी।
10. ट्रेन संख्या 09055 बांद्रा टर्मिनस–उधना स्पेशल 40 मिनट रेगुलेट होगी।
11. ट्रेन संख्या 19015 दादर–पोरबंदर सौराष्ट्र एक्सप्रेस 30 मिनट रेगुलेट होगी।

शॉर्ट टर्मिनेट/ओरिजिनेट होने वाली ट्रेनें:

1. 15 जुलाई, 2026 को यात्रा प्रारंभ होने वाली ट्रेन संख्या 19002 सूरत–विरार एक्सप्रेस पालघर स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी।
2. 15 जुलाई, 2026 को डोंबिवली से 05:49 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 61002 डोंबिवली–बोइसर मेमू वसई रोड स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी।
3. 15 जुलाई, 2026 को यात्रा प्रारंभ होने वाली ट्रेन संख्या 59039 विरार–वलसाड पैसेंजर पालघर स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं।